

अनुसूची 14-फारम सं०- 462

आदेश-पत्रक

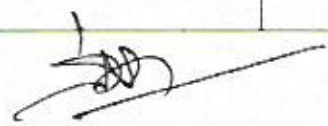
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक - ता०..... से तक

जिला..... सं०..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

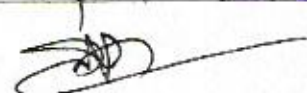
आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं०-11/2013 अपीलार्थी - कल्पना देवी बनाम रेस्पोंडेन्ट - राज्य सरकार</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रश्नगत ऑगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1709-1/प्रो० दिनांक 11.10.2012 के विरुद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।</p> <p>इस अपीलवाद में आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने दिनांक 28.08.2012 को 11:56 बजे पूर्वाह्न में सिमरी बख्तियारपुर परियोजना के चकभारौ पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र गाँधी चौक , एकपड़हा केन्द्र सं०- 17 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी, जो निम्न है:-</p> <p>(i) केन्द्र पर लाभुक बच्चें 23 उपस्थित पाये गये (ii) केन्द्र पर निरीक्षण के समय पोषाहार नहीं बन रहा था। (iii) स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र पर नहीं दी जा रही थी (iv) एक भी लाभुक बच्चें पोशाक में नहीं थें (v) तौल मशीन खराब था।</p>	



निरीक्षण के समय केन्द्र संचालन में उपरोक्त अनियमितताएँ के संबंध में केन्द्र की सेविका कल्पना देवी एवं सहायिका जानकी देवी के साथ ही महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती पुनीता कुमारी से भी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1378-1 दिनांक 31.08.2012 से अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु नोटिश किया गया तथा उसी पत्र में यह भी अंकित किया गया कि निर्धारित तिथि 7.09.2012 को सुनवाई होगी निर्धारित तिथि को सेविका/सहायिका ने अपना लिखित स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए अपना पक्ष रखा।

इस अपीलवाद की सुनवाई में अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया, एवं अपना-अपना पक्ष कागजात, प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने दिनांक 28.08.2012 को समय 11:56 बजे दिन में आँगनबाड़ी केन्द्र सं०-17 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय केन्द्र खुला था, सेविका/सहायिका दोनों अपने-अपने पोशाक में थी, निरीक्षण पंजी में निरीक्षी पदाधिकारी डी०पी०ओ० सहरसा ने जो आरोप लगाए हैं, एवं उस आरोप के आधार पर जो स्पष्टीकरण मांगे हैं वह निरीक्षण में लिखित नहीं है, जिससे पता चलता है कि वे दिल दिमाग में यह बात पहले से तय कर लिए थे कि सेविका को दंड देना है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किए हैं निरीक्षण के समय 23 बच्चें उपस्थित एवं 3 बच्चें अनामांकित उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण के समय उपस्थित पंजी में 29 बच्चें का उपस्थिति दर्ज था, जिसमें 23 बच्चें नामांकित का उपस्थित तो था ही शेष बचे 6 बच्चें अपना-अपना खाना के लिए थाली लाने, केन्द्र के बगल में स्थित अपना-अपना घर चले गये थे। सेविका के अनुरोध करने के उपरान्त भी डी०पी०ओ० कुछ मिनट रुककर केन्द्र पर से चले गये। केन्द्र पर उस दिन मीनू के अनुसार पोषाहार लाभुक बच्चें खाना खाए किसी भी लाभुकों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं किया। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः असत्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि डी०पी०ओ० सहरसा द्वारा लगाया गया आरोप कि स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र पर नहीं दी जा रही थी, वह भी सही नहीं है क्योंकि डी०पी०ओ० के निरीक्षण का समय 11:56 बजे दिन में था, जबकि स्कूल पूर्व शिक्षा का समय लाभुक को 09 बजे से 11:00 बजे दिन तक ही रहता है, 11:00 बजे तक लाभुक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा



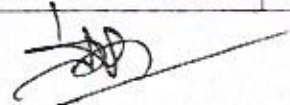
दे दिया गया था उसके बाद ही पूरक पोषाहार बनाने की तैयारी की गई थी।

उन्होंने (अपीलार्थी) के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आँगनवाड़ी केन्द्र पर पोषाहार नहीं बन रहा था, यह भी आरोप असत्य एवं गलत है, क्योंकि निरीक्षण समय बच्चों को भोजन कराने का समय था, एवं मीनू के अनुसार उस दिन रसिया बना हुआ था, जो निरीक्षण पदाधिकारी ने देखा भी था केन्द्र भवन में जगह के अभाव के कारण पोषाहार जो केन्द्र से सटे बगल में रखा हुआ था, जिसका उल्लेख आरोप पत्र में नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि एक आरोप यह भी लगाया कि एक भी बच्चें पोशाक में नहीं थे, इसके संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि पोशाक की राशि लाभुक बच्चों को नगद दी जाती है, केन्द्र के अधिकांश बच्चें महादलित समुदाय के हैं। वे उपलब्ध नगद राशि को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य मदों में खर्च कर देते हैं जिसकी जानकारी सेविका द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन में बराबर उच्चाधिकारी को दी जाती है, फिर भी बच्चें पोशाक में रहें इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। इस संबंध में लाभुक बच्चें एवं उनके अभिभावक को समय-समय पर पोशाक में रहने पर क्या फायदे होते हैं, जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोप यह भी लगाया गया कि तौल मशीन खराब होने की सूचना सेविका द्वारा लगाकर मासिक बैठक में की जाती रही है, जिसकी लिखित जानकारी भी सेविका ने डी०पी०ओ० साहेब को दिखाई थी, बावजूद आरोप सेविका पर लगाया गया है। जो गलत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका पर लगाए गए आरोप के संदर्भ में वहाँ के सी०डी०पी०ओ० मोनिका रानी एवं पर्यवेक्षिका पुनीता कुमारी से भी स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें दोनों ने लिखित तौर पर स्पष्ट रूप से वर्णित किए हैं कि केन्द्र सं०- 17 पर किसी भी तरह की अनियमितताएँ नहीं हैं अतः सेविका को आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण के समय केन्द्र खुला था 23 बच्चें लाभुक उपस्थित थे शेष बचे बच्चें 6 जिसकी उपस्थिति पंजी में उपस्थित दर्ज थी, खाना खाने के वास्ते अपने घर से वर्तन लाने गए थे, मीनू के अनुसार पोषाहार में रसिया बना था। जिसका पोषाहार की मात्रा का प्रतिशत 57.50% था स्कूल पूर्व शिक्षा भी दिया गया था, बच्चें



पोशाक में नहीं थे बच्चों पोशाक में रहे, सेविका द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। शेष अन्य आरोप जो लगाए हैं, वे खंडित, करने योग्य है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा (ज्ञापांक 1709-1/प्रो0 दिनांक 11.10.2012 में) सेविका के उपर लगाए गए 28740 रू0 में आर्थिक दंड काफी बड़ी राशि है, इतने बड़े आर्थिक दंड लगाने से सेविका के मनोबल पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, वे मुस्तैदी व लगन के साथ काम करने से आगे से परहेज करना शुरू करेंगी। उनका मनोबल कार्य करने से टुटेगा वे यह महसूस करेगी कि इतना मेहनत करने के उपरान्त भी अगर इतने बड़े आर्थिक दंड लगा ही दिया गया है तो मनोबल के साथ काम करने में अभिरुची कम हो जायेगी। अतः आर्थिक दंड को कम किए जाने की जरूरत है। अतः यह न्यायालय लगाए गए अन्य आरोपों के ऐवज में मात्र एक महीने का पूरक पोषाहार राशि आर्थिक दंड सेविका को देती है, ये आर्थिक दंड कोषागार में चलान द्वारा विभागीय शीर्ष में जमा किया जायेगा। साथ ही केन्द्र पर लाभुक बच्चों को जो पोशाक राशि मद में जो नगद राशि उसे दिये गए है अभिभावकों के संपर्क कर पोशाक क्य करवाना भी सेविका/सहायिका की जबाबदेही है, इससे वे मुकर नहीं सकती है। कम-कम एक -दो बच्चों से ही इसकी शुरुआत करें धीरे -धीरे यह कारवां आगे बढ़ता जायेगा। तौल मशीन की मरम्मति सरकार के द्वारा दिए गए राशि में होगा यह मरम्मति सेविका अपने मानदेय से नहीं कराईगी। चूँकि मानदेय की राशि भी सेविका को पर्याप्त नहीं मिलती है। जिससे मरम्मति भी कराया जाय, एवं परिवार का भरण- पोषण भी किया जाय। साथ ही सेविका (अपीलार्थी) को निर्देशित किया जाता है कि वे केन्द्र का संचालन काफी कुशलतापूर्वक निर्वहन आगे से करेंगी।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उप-निदेशक कल्याण

कोशी प्रमंडल, सहरसा

उप निदेशक कल्याण

कोशी प्रमंडल, सहरसा